

नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पुलिस की सर्वोच्च जिम्मेदारी : डॉ. यादव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कानून व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखना पुलिस का पहला कर्तव्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ितों के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए और उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शनिवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित आईजी कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ-2028 जैसे विशाल आयोजन की सफलता के लिए पुलिस को अभी से व्यापक तैयारियां करनी होंगी। भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और तकनीक



आधारित सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने साइबर अपराधों की रोकथाम,

महिला एवं बाल सुरक्षा, मानव तस्करी पर नियंत्रण और नशामुक्ति अभियान को पुलिस विभाग की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बदलते समय में साइबर अपराधों और संगठित

अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाना आवश्यक है। डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश पुलिस की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि मंडला और बालाघाट

जिलों को नक्सलवाद से मुक्त कर प्रदेश ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश नक्सलवाद का पूरी तरह उन्मूलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके लिए पुलिस और सुरक्षा बलों के प्रयास

प्रशंसनीय हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार पुलिस बल को मजबूत बनाने के लिए लगातार भर्ती कर रही है। अब तक 22 हजार पदों पर नियुक्तियों की जा चुकी हैं और स्वीकृत पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने थानों में बेहतर कार्य संस्कृति, नियमित निरीक्षण और प्रभावी पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक केलाश मकवाणा ने कहा कि सड़क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और नशे के विरुद्ध अभियान विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बाल सुरक्षा अभियान के तहत पिछले एक वर्ष में 14 हजार से अधिक नाबालिगों को संरक्षण और सहायता प्रदान की गई है।

गेहूं खरीदी में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई सहायक आपूर्ति अधिकारी निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: सागर जिले में गेहूं खरीदी के दौरान सामने आई अनियमितताओं के मामले में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री के निर्देश पर प्रथम दृष्टया आपूर्ति अधिकारी निशान्त पांडे को निलंबित कर दिया गया है। वहीं जिला आपूर्ति नियंत्रक ज्योति बघेल को सागर जिले के प्रभार से हटाकर भोपाल मुख्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। मामला गंधारिया के लक्ष्मी नगर स्थित श्री देव प्रभाकर हाउस वेयरहाउस से जुड़ा है, जहां गेहूं की बोरियों में मिट्टी मिलने की शिकायत सामने आई थी। प्रारंभिक जांच में कुछ बोरियों में गेहूं के स्थान पर अत्यधिक मात्रा में मिट्टी

पाए जाने की पुष्टि हुई है। इसके बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर संबंधित स्व-सहायता समूह के पदाधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मंत्री राजपूत ने कलेक्टर सागर को निर्देश दिए हैं कि उपार्जन कार्य से जुड़े अन्य विभागों के कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जाए। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों के साथ किसानों की सुरक्षा भी प्रकाश में रखना आवश्यक है। खाद्य मंत्री ने कहा कि सरकार खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

क्रूर कोर्ट ने माना निर्दोष

फिर भी पूर्व नेवी कमांडर पुर्णेंदु तिवारी जेल में क्यों?

परिवार ने मांगी प्रधानमंत्री मोदी से मदद



उल्लेख किया। जिसके फलस्वरूप सभी आठ अधिकारियों को माफ़ी मिल गयी थी एवं आठ में से 7 अधिकारी फरवरी 2025 में भारत लौट आये थे, लेकिन क्रूर में अलग वित्तीय जांच का सामना कर रहे कमांडर पुर्णेंदु तिवारी को भारत लौटने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें किसी अन्य प्रकरण का हवाला देते हुए 06 दिसम्बर 2025 को पुनः गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जबकि पुर्णेंदु तिवारी का उस मामले से कोई लेना देना नहीं था।

पुर्णेंदु तिवारी की बहिन मीतू भार्गव जो कि वर्तमान में ग्वालियर (म. प्र.) में रहती हैं ने प्रधानमंत्री से गुहार लगायी है कि आठ में से 7 अधिकारियों को भारत सरकार के प्रयासों से माफ़ी देकर रिहा कर भारत खाना कर दिया, किन्तु पुर्णेंदु तिवारी को विदा नहीं किया।

इस बीच 12 मार्च 2026 को पुर्णेंदु तिवारी को क्रूर सरकार के हाई कोर्ट द्वारा वित्तीय धोखा धड़ी मामले से पूरी तरह बरी किया, फिर भी वे दोहा की जेल में बंद हैं। परिवार ने पीएम नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्रालय से मदद मांगी है, परिवार ने भारतीय अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द उनकी वापसी सुनिश्चित करें।

भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों के चलते क्रूर के शेख तमीम बिन हमद अलधानी की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आठ नौ सेना के पूर्व अधिकारियों की रिहाई का मामला उठाया था। जिसमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, वीरेंद्र शर्मा, कमांडर पुर्णेंदु तिवारी कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर सुनानकर पकाला, अमित नागपाल और सेलर राकेश सम्मिलित थे। प्रधानमंत्री ने क्रूर में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा और दोनों देशों के मजबूत कूटनीतिक सम्बन्धों का

इटारसी में एंबुलेंस पर गिरा पेड़, कई स्थानों पर बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

भोपाल समेत कई जिलों में आंधी-बारिश

15 से 18 जून के बीच मानसून की संभावना

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्य प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन से पहले मौसम ने अचानक करवट ले ली है। शनिवार को राजधानी भोपाल सहित नर्मदापुरम, इटारसी, सीहोर, नरसिंहपुर, पचमढ़ी और पिपरिया समेत कई क्षेत्रों में तेज आंधी और बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। बारिश और तेज हवाओं का सबसे अधिक असर नर्मदापुरम जिले के इटारसी क्षेत्र में देखने को मिला। तेज आंधी के कारण कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए और बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। एक स्थान पर पेड़ एंबुलेंस पर गिर गया, जबकि बिजली विभाग का एक कर्मचारी हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गया। कई इलाकों में बिजली लाइनें



क्षतिग्रस्त हुईं और यातायात भी प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए भिंड, दतिया, छतरपुर, पना और सागर जिलों में

50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन,

सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट,

मंडला, डिंडौर, रीवा, सतना, शहडोल और अनूपपुर सहित कई जिलों में गरज-चमक और वर्षा का दौर जारी रहने का अनुमान

मुख्यमंत्री आज सागर जिले के केसली से करेंगे लाइली बहनों के खातों में राशि अंतरित

केसली में 190.85 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की देरों सौगात

लाइली बहना योजना की 37वीं किश्त की राशि का होगा अंतरण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 14 जून को सागर जिले के केसली विकासखंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाइली बहना योजना की 37 वीं किश्त बहना खातों के खातों में अंतरित करेंगे। इसमें एक करोड़ 25 लाख बहनों के खातों में 1835 करोड़ रुपये अंतरित किये जायेंगे। साथ ही देवरी विधानसभा को लगभग 190.85

करोड़ रुपये की लागत के 53 विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इनमें 122.02 करोड़ रुपये की लागत के 28 कार्यों का भूमि-पूजन और 68.83 करोड़ रुपये की लागत के 25 कार्यों का लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव क्षेत्र के विकास को गति देने वाले सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन करेंगे। इन विकास कार्यों से देवरी एवं केसली विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात



भोपाल: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मदेव प्रधान ने शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुख्यमंत्री निवास पर सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उनका पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया तथा बाबा महाकाल की प्रतिकृति प्रदान की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वैज्ञानिकों को दी बधाई

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सामरिक शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित बहु-स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली और मध्यम दूरी की एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मिसाइल प्रणाली की अभूतपूर्व सफलता के लिए डीआरडीओ के सभी वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

15 दिन में प्रगति नहीं तो ब्लैकलिस्ट होंगे रेड लिस्टेड सविदाकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने अमृत 2.0 के अंतर्गत संचालित जलप्रदाय परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रेड लिस्ट में शामिल सविदाकार यदि आगामी 15 दिनों में कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाते हैं, तो उनकी परफॉर्मंस गारंटी की कटौती की जाएगी और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित



परियोजनाओं के सविदाकारों पर विलंब डंड (एल.डी.) भी अधिरोपित किया जाएगा।

समीक्षा बैठक में अमृत 2.0 के तहत कम प्रगति वाली 122 परियोजनाओं की स्थिति, कार्य

गुणवत्ता और लंबित बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाए, ताकि निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरे हो सकें।

आयुक्त भोंडवे ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपलब्ध कराई गई राशि का 100 प्रतिशत उपयोग मार्च 2026 तक सुनिश्चित कर लिया गया है। बेहतर वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंधन के चलते मध्यप्रदेश अमृत योजना के अंतर्गत देश में सातवें स्थान पर पहुंच गया है। बैठक में विभागीय अधिकारियों, अभियंताओं और परियोजना प्रबंधन से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट में एमपी टूरिज्म को राष्ट्रीय सम्मान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने इवेंट, एक्जीक्यूशन और माइंस (मार्केटिंग, इंसिस्टेंस, कॉन्फ्रेंसिंग एंड एक्जीक्यूशन) प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक और राष्ट्रीय

उपलब्धि हासिल की है। मुंबई के सिडको एक्जीक्यूशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 10वें डेसेनियल एक्जीक्यूशन एक्सीलेंस अवार्ड्स-2026 में एमपी टूरिज्म को 'कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट में उत्कृष्टता' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

देश के इवेंट और कॉन्फ्रेंस सेक्टर के प्रतिष्ठित सम्मानों में शामिल इस पुरस्कार को पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक दिलीप कुमार यादव ने टीम के साथ ग्रहण किया। उन्होंने इस उपलब्धि को निगम की प्रतिबद्धता, व्यावसायिक

दक्षता और टीम वर्क का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पर्यटन लगातार अपने अधोसंरचना विकास, आतिथ्य सेवाओं और आयोजन क्षमताओं को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

संवाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मदेव प्रधान ने भोपाल स्थित शूटिंग अकादमी का किया दौरा...

नई शिक्षा नीति से खेल और शिक्षा को मिल रही नई दिशा : प्रधान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मदेव प्रधान ने शनिवार को भोपाल स्थित शूटिंग अकादमी का दौरा कर खिलाड़ियों से संवाद किया। इस दौरान उनके साथ खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने खिलाड़ियों के अनुभव जानने के साथ देश में खेल और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलावों पर चर्चा की।

श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कौशल विकास, खेल और नवाचार को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने का व्यापक प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से खेलों और शारीरिक शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई और खेल दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं।

उन्होंने बताया कि एपीएआर आईडी के जरिए विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को शैक्षणिक तथा खेल संबंधी उपलब्धियों का समार रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। साथ ही

खेल गतिविधियों को अकादमिक क्रेडिट प्रणाली से जोड़ने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में

स्पोर्ट्स कोटा लागू किया जाना खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधान ने वर्ष 2036 आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में

लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं की भागीदारी से भारत खेल और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में वैश्विक पहचान बनाएगा। उन्होंने आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को निर्णायक बताया।

श्री सारंग ने केंद्रीय मंत्री को मध्यप्रदेश की खेल उपलब्धियों और शूटिंग अकादमी की विशेषताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भोपाल की शूटिंग अकादमी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। यहां आयोजित ओलंपिक ट्रायलस इसकी उत्कृष्ट व्यवस्थाओं का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

उद्यमियों को प्रोत्साहन राशि, भू-आवंटन पत्र और हितलाभ का वितरण आज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: प्रदेश में उद्यमिता को नई दिशा देने के साथ रोजगार सृजन को गति प्रदान कर 'विकसित मध्यप्रदेश' बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए विचार 14 जून को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में वृहद कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विभिन्न जिलों के एमएसएमई उद्यमियों, स्टार्ट-अप तथा अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान उद्यमियों को भू-आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न लाभ और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को हितलाभ भी वितरित किए जाएंगे।

कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप भी उपस्थित रहेंगे। डॉ. यादव इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए एमएसएमई उद्यमियों एवं स्टार्टअप प्रतिनिधियों से सीधा संवाद भी करेंगे। संवाद के माध्यम से उद्यमी अपने अनुभव साझा करेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों और योजनाओं के प्रभाव के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही वे उद्यमिता को और अधिक सरल, सुलभ एवं प्रभावी बनाने के लिए अपने वितरण करेंगे। इस दौरान उद्यमियों को भू-आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न लाभ और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को हितलाभ भी वितरित किए जाएंगे।